Indian Council of World Affairs
Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi

आईसीडब्ल्यूए अतिथि खंड

गुटनिरपेक्ष आंदोलन - वेनेजुएला
क्या अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है?

राजदूत डॉ. भास्कर बालकृष्णन

3 फरवरी 2016

गुट-निरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) का अगला (17वां) शिखर सम्मेलन वेनेजुएला में होना है। 2012 में स्थापित गुट-निरपेक्ष की आवर्तनशील प्रथा और ईरान में हुए पिछले शिखर सम्मेलन में लिए गए फैसले के तहत यह देश अगले तीन सालों के लिए ईरान से गुट-निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता का जिम्मा प्राप्त करेगा। इसलिए वेनेजुएला की स्थिति, (जहां दिसंबर 2015 के विधानसभा चुनावों में शावेज से प्रेरित पीएसयूवी पर विपक्षी दक्षिणपंथी एमयूडी गठबंधन ने निर्णायक जीत हासिल की) पर कड़ी नजर रखी जाएगी। क्या वेनेजुएला गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कर सकेगा और गुट-निरपेक्ष के नेतृत्व की जिम्मेदारी ले पाएगा?

पिछले 3 सालों से गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन काफी नियमित रूप से आयोजित किया गया है। अपवाद भी थे; 1964-70 (जब जाम्बिया ने मिस्र से इसका जिम्मा लिया था), और 1979-83, जब भारत ने क्यूबा से पदभार ग्रहण किया। बाद वाली स्थिति इसलिए पैदा हुई, क्योंकि इरान के साथ संघर्ष के कारण इराक 1982 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं कर सका, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मार्च 1983 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए सहमति जाहिर की। वेनेजुएला की स्थिति की कारण पहले ही 2015 में होने वाला 17वां शिखर सम्मेलन का मूल कार्यक्रम स्थगित होने के बाद 2016 एक तारीख तय की गई है। विदेश मंत्री स्तर की समन्वयक ब्यूरो की महत्वपूर्ण बैठक, जो आमतौर पर शिखर सम्मेलन के नतीजों की रिपोर्ट तैयार करती है, को नई तारीख की घोषणा किए बगैर स्थगित कर दिया गया है।

मौजूदा समय में गुट-निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 120 और पर्यवेक्षक देश 16 हैं और हरेक शिखर सम्मेलन में कई मेहमान देश निर्धारित किए जाते हैं। हितों के मद्देनजर क्षेत्रीय विखंडन है। अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में सभी 53 अफ्रीकी देशों का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व दिया गया है। एशिया के साथ ओशिनिया के 40 पूर्ण सदस्य हैं, और चार पर्यवेक्षक (चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान और ताजिकिस्तान) हैं। अमेरिका के 26 सदस्य हैं और 7 पर्यवेक्षक (अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, मैक्सिको, पैराग्वे और उरुग्वे) हैं। यूरोप में केवल एक सदस्य (बेलारूस) और 4 पर्यवेक्षक (आर्मेनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और यूक्रेन) हैं। 1992 के बाद किसी भी यूरोपीय देश ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की है, इसकी अध्यक्षता एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के क्षेत्रों में घूमाती रही है।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन का सबसे मजबूत आधार अफ्रीका में है, इसके बाद एशिया में और अमेरिका में इनसे कमजोर है। शायद अमेरिका, जो लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रमुख शक्ति के रूप में रहा है, के प्रभाव के कारण कई प्रमुख लैटिन अमेरिकी देश पर्यवेक्षक बने हुए हैं, और एनएएम को मूलतया सोवियत संघ का समर्थक माना जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ सोवियत संघ के टूटने और चीन के उदय के साथ, गुट-निरपेक्ष आंदोलन कैसी भूमिका अदा करे, को लेकर व्यापक रूप से चर्चा और बहस हुई है। उभरने वाले सामान्य सूत्र से ऐसा लगता है कि एक या कुछ देशों के प्रभुत्व के खिलाफ और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में लोकतंत्र के लिए, राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में आंदोलन को एक ताकत बनना चाहिए। इस अर्थ में गुट-निरपेक्ष आंदोलन सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सुधार के लिए आवाज उठाने और इस मांगों का समर्थन करने के लिए एक मंच भी है।

इसके अलावा गुट-निरपेक्ष प्रवर्तन प्रणाली और नियामक एजेंसियों को मजबूत करने के पक्ष में, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के विकासोन्मुख एजेंसियों और कार्यक्रमों को समाप्त करने की प्रवृत्ति का मुकाबला कर सकता है। यह पिछले एक दशक से अमेरिका, ब्रिटेन और कई ओईसीडी देशों द्वारा ऐसा किया गया है। दक्षता में सुधार, नकल को कम करने और द्विपक्षीय चैनलों के माध्यम से विकास को बेहतर तरीके से संभालने के लिए जोर दिया जा सकता है, के नाम पर इस प्रयास को बड़ी सावधानी से अंजाम दिया जाता है। यूएनआईडीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, यूनेस्को और एफएओ सभी इस हमले के निशाने पर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, आईएईए जैसी एजेंसियों को अनुकूल उपचार दिया गया है, क्योंकि वे एनपीटी जैसे असमान संधियों के माध्यम से क्षमता के मौजूदा संतुलन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं और आईएईए के भीतर भी विकास को कम करने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग की जाती है।

टकराव और समस्याएं और भी हैं, जो चिंता के गंभीर विषय हैं। इनमें अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया में संघर्ष और दूसरे कई देशों में आतंकवाद का प्रसार शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों सहित कुछ प्रमुख शक्तियों के भूस्थिर हितों को बनाए रखने के कारण समाधान नहीं खोज पाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों समेत कुछ प्रमुख शक्तियों के भू-रणनीतिक हितों को देखते हुए इसका समाधान खोजने में सक्षम नहीं हैं। राष्ट्र की विफलता का रोग कई राष्ट्रों तक फैल रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अशांत स्थिति में है, वहीं दुनिया भर में विकास का व्यापक अभाव है। मानवता के सामूहिक अस्तित्व की रक्षा के मद्देनजर जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान के लिए सरकारों को मिलकर काम करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन समृद्ध राष्ट्र आवश्यक बलिदान करने को तैयार नहीं हैं। विकासशील देशों में इबोला जैसी बीमारी के प्रकोप का जवाब देने में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की विफलता को सामने लाया। इसे स्थिति को देखते हुए, गुट-निरपेक्ष को वैश्विक मुद्दों के समाधान में एक उपयोगी भूमिका निभानी चाहिए।

तेल की कीमतों में गिरावट ने वेनेजुएला को बड़ा झटका दिया है और इसे आर्थिक आपातकाल में धकेल दिया है और ऋणों पर आसन्न संप्रभु डिफ़ॉल्ट की संभावना को बढ़ा दिया है। विश्लेषकों के अनुसार कीमतों में उथल-पुथल के बीच वेनेजुएला तथाकथित कमजोर पांच ओपेक सदस्यों (लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया और इराक सहित) में से एक है। प्रति बैरल पर 30 अमेरिकी डॉलर पर वेनेज़ुएला तेल निर्यात से आय का 90% का उपयोग बाहरी लेनदारों को सेवा ऋण चुकाने के लिए करेगा। इसने तेल की कीमतों में गिरावट का मुकाबला करने के लिए ओपेक की एक आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की है, लेकिन कुछ प्रमुख तेल निर्यातकों के साथ जाने की संभावना नहीं है। निकोलस मादुरो (चावेज़ के उत्तराधिकारी) के नेतृत्व वाली सरकार और राष्ट्रपति के बीच आंतरिक विभाजन और संसद में एमयूडी के वर्चस्व वाले (167 सीटों में से 105 सीटों के साथ) विपक्ष द्वारा हिंसा और विरोध-प्रदर्शन तेज होने की संभावना है। हो सकता है आर्थिक आपातकाल की घोषणा और सख्त कराधान के उपायों के बारे में अटकलों के परिणामस्वरूप पूंजी की कमी और अस्थिरता का अंदेशा होने लगा। वर्तमान संकट के कारण पैदा हुई अस्थिरता का ठिकरा पश्चिम के सिर पर मढ़ने के सरकारी के इरादे से कोई मदद नहीं मिलने वाली है।

इस स्थिति में गुट-निरपेक्ष जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी करने में सरकार का सक्षम होना मुश्किल है। यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वेनेजुएला को अपने बाहरी लेनदारों से राहत मिल सकता है या वह पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण को सुरक्षित कर सकता है। हालांकि यह वेनेजुएला की सरकार पर निर्भर करेगा कि वह गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित कर सकती है या यह अनुरोध कर सकती है कि एक दूसरा मेजबान देश उसे मिल जाए, जिसके लिए आगे परामर्श की आवश्यकता होगी। लैटिन अमेरिका में गुटनिरपेक्ष की कमजोरी को देखते हुए इस क्षेत्र से कोई दूसरा मेजबान देश मिलना मुश्किल होगा। शायद वर्तमान अध्यक्ष क्यूबा और ईरान इस संबंध में मादुरो सरकार से परामर्श कर सकते हैं और स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ़ सकते हैं।

***